COP25 जलवायु बैठक के एजेंडे पर क्या है?

लेखक - अमिताभ सिन्हा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

30 नवंबर, 2019

"मैड्रिड में अगले दो हफ्तों के लिए खतरे का संकेत देने वाले जलवायु रिपोर्टों की एक श्रृंखला की छाया में COP25 आयोजित किया जाएगा। क्या इन रिपोर्टों से देश दबाव में आएंगे?"

संक्षिप्त नाम COP25 नाम से जाना जाने वाला दो सप्ताह का वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सोमवार को नए चेतावनियों के साथ मैड्रिड में शुरू होने वाला है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन के भयावह प्रभावों से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) और अन्य एजेंसियों की रिपोर्टों की एक श्रृंखला यह दोहराती रही है कि जब तक देश अपने कार्यों को महत्त्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ाते हैं तब तक पूर्व-औद्योगिक रुझानों की तुलना में 2° C के भीतर औसत वैश्विक तापमान रखने की बहुत कम उम्मीद है।

हालाँकि, यह जलवायु परिवर्तन वार्ताकारों के एजेंडे पर सीधे नहीं होगा, जो मैड्रिड में 2015 के पेरिस समझौते के नियम-पुस्तिका को पूरा करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ बैठक करेंगे ताकि यह अगले साल से लागू हो जाए।

ये रिपोर्ट किन मुद्दों को उजागर कर रही है?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निर्मित वार्षिक उत्सर्जन गैप रिपोर्ट से सबसे सख्त और हालिया चेतावनी आई है, जो कहती है कि पूर्व-औद्योगिक समय से 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर औसत तापमान रखने का लक्ष्य पेरिस समझौते में निहित एक आकांक्षात्मक लक्ष्य 'असंभव बनने की कगार पर' था। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 25 बिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर नहीं होना चाहिए वर्तमान उत्सर्जन की वृद्धि दर से, उस समय तक कुल 56 बिलियन टन को छूने का अनुमान है, जो दुगने से भी अधिक है।

तदनुसार दुनिया को अब और 2030 के बीच हर साल अपने उत्सर्जन को कम से कम 7.6% तक कम करने की आवश्यकता है जो कि 25 बिलियन-टन के स्तर तक पहुँच सकता है। यह देखते हुए कि समग्र उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है, इस तरह की बड़ी कटौती की बहुत संभावना नहीं है जब तक कि देश पूरी तरह से कठोर कदम नहीं उठाते हैं।

इस बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का वायुमंडलीय सांद्रता 2018 में नए रिकॉर्ड तक पहुँच गया है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता 2018 में 407.8 भागों प्रति मिलियन तक पहुँच गई, जो पिछले वर्ष 405.5 पीपीएम थी। यह 1750 के पूर्व-औद्योगिक स्तर का 147% थी। मीथेन की सांद्रता 1750 के स्तर का 259% थी जबकि नाइट्रस ऑक्साइड 123% से ऊपर था।

इस साल 18 मई को दैनिक औसत कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता ने पहली बार 415 पीपीएम को छू लिया। तब से यह उस स्तर से नीचे आ गया है।

पिछले कुछ महीनों में कई अन्य रिपोर्टें आई जिनमें IPCC द्वारा तीन विशेष रिपोर्टें और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतरसरकारी विज्ञान-नीति मंच द्वारा प्रकृति की स्थिति पर एक और प्रमुख रिपोर्ट, सभी ने बिगड़ते परिदृश्य की ओर इशारा किया है।

हालाँकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैड्रिड में बैठक करने वाले देशों पर अपने प्रयासों को बढ़ाने का दबाव होगा और उनमें से कुछ वास्तव में अपने लिए कुछ अतिरिक्त उपायों या लक्ष्यों की घोषणा कर सकते हैं। वास्तविक वार्ता प्रक्रिया पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका के अनसुलझे मुद्दों को निपटाने के बारे में है।

नियम पुस्तिका जिसमें प्रक्रिया, तंत्र और संस्थान शामिल हैं जिसके माध्यम से पेरिस समझौते के प्रावधानों को लागू किया जाएगा, को पिछले साल काटोविस में अंतिम रूप दिया गया था। लेकिन कुछ मुद्दे अनसुलझे रह गए थे और वार्ताकारों को अगले एक साल में निपटाने के लिए छोड़ दिया था। सबसे महत्त्वपूर्ण पेरिस समझौते के तहत् बनाए जाने वाले नए कार्बन बाजारों से संबंधित विवाद से संबंधित है।

एक कार्बन बाजार देशों या उद्योगों को उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है। इन क्रेडिट को मुद्रा के बदले उच्चतम बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है। कार्बन क्रेडिट के खरीदार उत्सर्जन में कमी को अपने रूप में दिखा सकते हैं और उनका उपयोग अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।

1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत् पहले से मौजूद एक कार्बन मार्केट, पहले के जलवायु समझौते जो अगले साल तक समाप्त हो जाएंगे और पेरिस समझौते द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे। पिछले एक दशक में जैसा कि कई देश क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर चले गए और कोई भी अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहा था। कार्बन क्रेडिट की माँग कम हो गई थी। परिणामस्वरूप भारत, चीन और ब्राजील जैसे विकासशील देशों ने भारी मात्रा में कार्बन क्रेडिट जमा किया था। ये क्रेडिट अब व्यर्थ हो जाएंगे इसकी संभावना बढ़ गई है।

पहले से संचित कार्बन क्रेडिट का क्या होता है?

ब्राजील यह तर्क देता रहा है कि इन संचित कार्बन क्रेडिट को नए कार्बन बाजार के अंतर्गत मान्य किया जाना चाहिए लेकिन विकसित देशों ने इसका विरोध करते हुए दावा किया है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत् कमजोर सत्यापन तंत्र ने संदिग्ध परियोजनाओं को क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति दी थी। भारत, जिसने 750 मिलियन प्रमाणित उत्सर्जन में कटौती (सीईआर) जमा की है, इस पर ब्राजील की स्थिति का समर्थन कर रहा है।

इस झगड़े का समाधान मैड्रिड बैठक की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण है लेकिन अन्य लंबित मुद्दे भी हैं जैसे प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सूचना की रिपोर्टिंग के तरीके आदि। विकासशील देश यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेंगे कि नुकसान और क्षति के मुद्दे की अधिक प्रशंसा और मान्यता हो। वे चक्रवात या बाढ़ जैसी जलवायु परिवर्तन से प्रेरित घटनाओं के कारण बड़े नुकसान उठाने वाले देशों की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

देशों द्वारा प्रतिबद्धताओं के बारे में?

यह सम्मेलन उस संकल्प के लिए सबसे उत्सुकता से देखा जाएगा जो देश जलवायु परिवर्तन से लड़ने के अपने प्रयासों को बढ़ाने में उत्सुकता दिखाते हैं। पिछले कुछ महीनों में देशों पर और अधिक प्रयास करने का दबाव बढ़ा है, विशेष रूप से बड़े उत्सर्जक वाले देशों पर। इस दबाव के कारण कम से कम कुछ देशों में सकारात्मक परिणाम मिले हैं जो दीर्घकालिक कार्य योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक कुल 71 देशों ने जिनमें से अधिकांश छोटे उत्सर्जक हैं, ने 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है।

उम्मीद है कि कुछ और देश मैड्रिड सम्मेलन में ऐसा करेंगे। हालाँकि, सबसे महत्त्वपूर्ण खिलाड़ियों - चीन या भारत - द्वारा व्यापक रूप से अपने लक्ष्यों को बढ़ाने की घोषणा नहीं करने की संभावना अधिक है। ये देश तर्क देते रहे हैं कि उनके वर्तमान प्रयास पहले से ही बहुत अधिक हैं जबकि कई अन्य अमीर और विकसित देश हैं, जो मुख्य रूप से जलवायु समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे अनुपातिक रूप से कम प्रयास कर रहे हैं, साथ ही वे कम विकसित देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने में भी सहायता नहीं कर रहे हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1- **COP25 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए:**

1. COP25 का आयोजन स्पेन के शहर मैड्रिड में किया जायेगा।
2. इस वार्ता प्रक्रिया में 2015 के पेरिस समझौते के अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा होगी।

कूट:-

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context of COP-25 indentify the correct statement.**

1. COP-25 will be held in the Madrid city Span
2. In this negotiation process unresolved issues of the 2015 Paris Agreement will be discussed

Code:

(a) 1 and 2

(b) Only 1

(c) 2 and 3

(d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'कॉप-25 की प्रस्तावित बैठक की सफलता तभी सम्भव है, जब सभी देश हालिया प्रकाशित रिपोर्टों में सामने आई चिंताओं को दूर करने की सामूहिक कोशिश करें।' इस कथन का विश्लेषण करें।

(250 शब्द)

'The success of the proposed meeting of COP-25 is possible only when all the countries make collective efforts to address the concerns mentioned in the recent published reports.' Analyze this statement.

(250words)

नोट : 29 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।